(ii) रेल इंजनों पर डीजल की खपत की ड्राइवर-वार और इंजन-वार निगरानी रखना ।

(iii) रेल इंजनों की सही यांत्रिक हालत में रखने के लिए निगरानी रखना।

(i) रेलपथ और पहिया कोरों आदि का स्नेहन ।

(ग) पैट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के के लिए रेलों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गैर-कर्षण प्रयोजनों के लिए पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में पर्याप्त कमी हुई है ।

1989-90 में कर्षण के लिए डीजल तेल की खपत में 1987-88 अर्थात् 2 वर्षों की तुलना में केवल 5% की वृद्धि हुई है, यद्यपि इसी अवधि के दौरान डीजल रेल इंजन में 9 12 % की वृद्धि हुई है । वास्तव में, कर्षण के लिए डीजल के कुशल उपयोग के लिए रेलों द्वारा किए गए विभिन्न उपचारात्मक उपायों के कारण 1989-90 में प्रति इंजन उच्च गति डीजल तेल की खपत 1987-88 की तुलना में 3 7% कम हुई है ।

1990-91 के पहले छ. महीनों के दौरान भी उच्च गति डीजल तेल की खपत में वही है जो मौजूदा बेड़े में 86 डीजल रेल इंजन शामिल करने के बावजूद पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में थी।

US Assistance to develop religious Places of Buddhists

1065. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether U.S. has offered assistance to India to develop religious places of Buddhists interests in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SMT USHA SINGH) (a) and (b) National Park Service of U S A are preparing a conceptual plan for the development of selected places along the Buddhist Sector at Sarnath in Uttar Pradesh and Bodhgaya, Rajgir and Nalanda in Bihar

रीवा कृषि महाविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

1066 श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार कृषि महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती लाल बीरचन्दभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) मध्य प्रदेश में पहले से ही दो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनके अंतर्गत 13 संघटक महाविद्यालय है ।

मध्य प्रदेश में दल्ली-राजहरा जगदलपुर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का पूरा किया जाना

1067 **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में दल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेलवे लाइन के संबंध में अंतिम सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास): (क) से (ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अनुरोध पर दल्ली-राजहरा-से जगदलपुर सिलकजोहरी/दंतेवाड़ा तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया गया था और प्रत्येक प्रस्ताव की लागत 87–88 के मूल्य स्तर पर लगभग 500 करोड़ रुपए आंकी गयी थी ।

जगदलपुर तक लाइन का निर्माण करने के लिए अपेक्षित उच्च पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए, इस्पात और खान मंत्रालय तथा सेल ने योजना आयोग के परामर्श से फिलहाल भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की सप्लाई करने के लिए रावघाट तक लाइन का निर्माण करने का विकल्प दिया है । चूंकि दल्ली रा-जहारा से रावघाट तक रेलवे लाइन (95 कि० मी०, 87-88 के मूल्य के आधार पर लागत 88 35 करोड रुपए) की व्यवस्था केवल भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क के परिवहन हेतु की जानी है, इसलिए इसका निर्माण तभी किया जा सकता है जब पर्यावरण और वन मंत्रालय, द्वारा परियोजना को स्वीकृति दे दी जाए तथा इस्पात एवं खान मंत्रालय तथा सेल निर्माण की लागत वहन करने के लिए सहमत हो जाये ।

Supply of additional edible oils to Tamil Nadu

1068. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Tamil Nadu Government has urged to supply additional quantity of edible oils to the State so as to bring down the high prices of oil;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken thereon?

THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SARWAR HUSSAIN): (a) and (b) Tamil Nadu Government has requested for allotment of 13,000 MTs. edible oils per month for distribution to the cardholders in the State at the rate of 1 kg. per card per month.

(c) The allocation of imported edible oils to States/UTs is made on month to month basis depending on various factors such as demand, availability of oils with State Trading Corporation, availability of edible oils in open market etc.

अधिप्राप्ति मूल्य

1069. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के लिए सरकार ने विभिन्न फसलों का थोक अधिप्राप्ति मूल्य किस दर पर निर्धारित किया है ; और

(ख) सरकार ने उपरोक्त दरों पर विभिन्न स्थानों पर कितनी कितनी मात्रा में खरीदारी की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) सरकार द्वारा खरीफ़/रबी विपणन मौसम 1990-91 के दौरान गेहूं, धान और मोटे अनाजों के निर्धारित किए गए वसूली (समर्थन) मूल्य निम्नानुसार हैं :—

जिन्स	वसूली मूल्य
	(रु प्रति क्विंटल)
गेहूं	215/–
धान	
साधारण	205/–
बढ़िया	215/–
उत्तम	225/–
मोटे अनाज	180/–
(मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी)	

(ख) विवरण संलग्न है ।